

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अभय कुमार एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 411/2021

18 नवंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार वर्मा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या हत्या के अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि संधारणीय है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता---धारा 302---- प्राथमिकी और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का प्रभाव---संयोग गवाहों और संबंधित/हितधारक गवाहों की गवाही का साक्ष्य मूल्य---हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मृतक पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने का आरोप है।

निर्णय: वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चल रही थी--- हालांकि घटनास्थल पुलिस स्टेशन से केवल 100 गज की दूरी पर है और पुलिस उस अस्पताल में पहुंच गई थी जहां पोस्टमार्टम किया गया था, एफआईआर दर्ज करने में एक दिन की देरी अभियोजन पक्ष के मामले को झटका देती है क्योंकि इससे संदेह पैदा होता है कि क्या एक दिन बाद दर्ज की गई लिखित रिपोर्ट राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अपीलकर्ताओं के निहितार्थ के बारे में परामर्श और कई विचारों के बाद ही थी---घटना के सभी प्रत्यक्षदर्शी इस मामले के संयोग-साक्षी प्रतीत होते हैं---कानून बहुत स्पष्ट है कि केवल इसलिए कि एक गवाह ने घटना को संयोग से देखा है, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है, हालांकि कई बार इसकी अधिक सावधानी से जांच करने की आवश्यकता होती है---इस मामले में, सभी संयोग गवाहों ने घटना के कई दिनों के बाद पुलिस के सामने अपने बयान दिए हैं और उनके बयान भी मुखबिर द्वारा लिए गए मूल अभियोजन पक्ष के मामले से भिन्न हैं---धारा 161 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी, हालांकि वे गवाह जांच के लिए उपलब्ध थे या हो सकते थे जब जांच अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया या उसके तुरंत बाद

अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है----एक संयोग गवाह के साक्ष्य के लिए बहुत सावधानी और करीबी जांच की आवश्यकता होती है और एक संयोग गवाह को पी.ओ. में अपनी उपस्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट करना चाहिए----घटना के बाद संयोग गवाह के आचरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से कि क्या उसने अपने गांव या पड़ोस में किसी और को घटना के बारे में सूचित किया था---हालांकि मृतक के बड़े भाई, मुखबिर ने स्थानीय राजनीति में खुद को मजबूत करने के लिए मृतक की हत्या में अपनी रुचि होने के सभी सुझावों से इनकार किया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वह अपीलकर्ताओं को फंसाने के लिए एक मकसद रख रहा था----जहां गवाह पीड़ित का करीबी रिश्तेदार है और हमलावर के प्रति पीड़ित की दुश्मनी को साझा करता है, तो स्वाभाविक रूप से आपराधिक न्यायालयों के लिए ऐसे गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य की बहुत सावधानी से जांच करना और उस पर भरोसा करने का फैसला करने से पहले उस साक्ष्य में सभी कमजोरियों की जांच करना आवश्यक हो जाता है---तथ्य यह है कि मुखबिर ने पुलिस को मामले की सूचना देने का चुनाव नहीं किया, तब भी जब पुलिस पार्टी आपातकालीन वार्ड में पहुंची और हत्या के आठ महीने के भीतर, वह अपने छोटे भाई, मृतक के स्थान पर प्रमुख के पद पर भी निर्वाचित हो गया, जो एक साथ मिलकर यह धारणा देता है कि मुखबिर पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है----अभियोजन पक्ष के मामले में स्पष्ट असंगतताएं और भौतिक विसंगतियां अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप को अत्यधिक संदिग्ध बनाती हैं--- अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार माना गया----निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश रद्द किया गया----अपील स्वीकार की गई। (पैरा- 17- 19, 30, 33, 38, 43, 50, 51, 57, 63)

न्याय दृष्टान्त

ए.पी. राज्य बनाम के. श्रीनिवासुलु रेड्डी; (2003) 12 एससीसी 660; जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2009) 9 एससीसी 719; सच्चे लाल तिवारी बनाम यू.पी. राज्य; (2004) 11 एससीसी 410; पूरन बनाम पंजाब राज्य; (1952) 2 एससीसी 454; गणेश भवन पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य; (1978) 4 एससीसी 371; दरिया सिंह बनाम पंजाब राज्य; एआईआर 1965 एससी 328पर भरोसा किया गया।

बालकृष्ण स्वैन बनाम उड़ीसा राज्य, (1971) 3 एससीसी 192; मारुति रामा नाइक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2005) 3 एससीसी 689संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता; दंड प्रक्रिया संहिता, शस्त्र अधिनियम।

मुख्य शब्दों की सूची

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---हत्या---संयोग गवाहों की गवाही---प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही---संबंधित/इच्छुक गवाहों की गवाही---एफआईआर दर्ज करने में देरी---गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी---झूठे आरोप लगाने की मंशा---संदेह का लाभ।

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र परीक्षण संख्या 280/2019 में हाजीपुर में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, वैशाली द्वारा दिनांक 15.03.2021 को दोषसिद्धि और सजा का आदेश, जो जंदाहा पी.एस. केस संख्या 202/2018 से उत्पन्न हुआ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 411/2021 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री अरविंद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 411/2021**

थाना कांड सं.-202 वर्ष-2018 थाना-जंदाहा जिला-वैशाली से उत्पन्न

- =====
1. अभय कुमार @अभय साहनी, राम बाबू साहनी के पुत्र, निवास का ग्राम-दुलौर, थाना.-
जंदाहा , जिला-वैशाली।
 2. राम बाबू साहनी, राम धारी साहनी के पुत्र, निवास का ग्राम-दुलौर, थाना.-जंदाहा , जिला-
वैशाली।

..... अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार सरकार

..... उत्तरदाता/ओं

के साथ

आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 322/2021

थाना कांड सं.-202 वर्ष-2018 थाना-जंदाहा जिला-वैशाली से उत्पन्न

=====

जय शंकर चौधरी, उपेंद्र साह @शंकर चौधरी @उमेश चौधरी के पुत्र, निवास का ग्राम-अरनिया,
थाना- जंदाहा , जिला वैशाली।

..... अपीलार्थी/एस

बनाम

बिहार सरकार

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

(2021 के आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 411 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री अरविंद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

(2021 के आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 322 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री बिमल कुमार, अधिवक्ता

श्री वसंत विकास, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार वर्मा

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तारीख:18-11-2024

दोनों अपीलों को एक साथ सुना गया है।

2. हमने अपीलार्थियों/अभय कुमार @अभय साहनी और राम बाबू साहनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय सिंह को 2021 की आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 411 और, अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी के विद्वान अधिवक्ता श्री बिमल कुमार को 2021 की अपील (डी. बी.) संख्या 322 में सुना है।

3. अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी और अभय कुमार उर्फ अभय साहनी को भा. द. सं. की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया है और अपीलार्थी/राम बाबू साहनी को भा. द. सं. की धारा 302/34 के तहत हाजीपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, वैशाली द्वारा जंदाहा थाना कांड सं.-202 वर्ष-2018 से उत्पन्न 2019 के सत्र परीक्षण संख्या 280 में दोषी ठहराया गया है। दिनांक 15.03.2021 के आदेश द्वारा, तीनों अपीलार्थियों को भा. द. सं. की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और अपीलार्थियों/जय शंकर चौधरी और अभय कुमार उर्फ अभय साहनी को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक अपीलार्थियों को भा. द. सं. की धारा 302 के तहत 50, 000/- रुपये का जुर्माना देने का निर्देश

दिया गया है। जुर्मने का भुगतान न करने पर छह महीने के लिए सश्रम कारावास भुगतान होगा।

4. मृतक के बड़े भाई (पीडब्लू 7) ओम प्रकाश साहनी ने 14.08.2018 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13.08.2018 को उनके भाई मनीष कुमार (मृतक) को स्थानीय बीडीओ ने उनके घर बुलाया था। बाद में, जब मृतक बीडीओ के घर से वापस आया और प्रखण्ड प्रमुख के कक्ष में प्रवेश करने ही वाला था, तो अपीलार्थी/राम बाबू साहनी ने उसे मारने का आदेश दिया। उसके आदेश पर, अपीलकर्ताओं/जय शंकर चौधरी और अभय कुमार ने मृतक पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। इसके बाद दोनों हमलावर मोटरसाइकिल से घटनास्थल से निकल गए। एक अन्य मोटरसाइकिल पर, अपीलार्थी/राम बाबू साहनी और बिनोद चौधरी घटनास्थल से भाग गए।

5. पी. डब्ल्यू. 7 और अनिल कुमार साहनी (पी. डब्ल्यू. 2), जो उस समय मृतक के चालक थे, दूसरों की मदद से मृतक को डॉ. बिंदु झा के क्लीनिक में ले आए, जहाँ से उसे उपचार के लिए एक उच्च केंद्र में भेजा गया। इसके बाद मृतक को एक निजी अस्पताल यानी गणपति अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

6. इसके बाद शव को हाजीपुर के सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस बीच पुलिस दल भी आ गया था।

7. हत्या का कारण बताते हुए, पीडब्लू 7 ने लिखित रिपोर्ट में कहा है कि 02.08.2018 पर, अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी जो प्रमुख का प्रभार संभाल रहे थे, के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मंचन किया गया था। उस कार्यवाही में, अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी मृतक से आठ मतों से हार गए थे। पी. डब्ल्यू. 7 को मनोर के स्थानीय विधायक उमेश सिंह कुशवाहा, बिनोद चौधरी, अजीत कुमार और अन्य लोगों द्वारा चुनाव के बाद गंभीर परिणाम

भुगतने की धमकी दी गई थी और कहा गया था कि मृतक को प्रमुख के रूप में जारी नहीं रहने दिया जाएगा।

8. यही वह कारक था जिसने मृतक की हत्या के लिए काम किया था।

9. पूर्व-उल्लिखित लिखित रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 302,120 (बी) और 506/34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत जांच के लिए 2018 का जंदाहा थाना कांड संख्या 208 दिनांक 14.08,2018 दर्ज किया गया था।

10. पुलिस ने जाँच के बाद अपीलार्थियों और पाँच अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

11. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों से पूछताछ करने के बाद केवल अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर कहा गया है, लेकिन बाकी पांच व्यक्तियों को बरी कर दिया, जिन पर भी अपीलार्थियों के साथ मुकदमा चलाया गया था।

12. मृतक की मृत्यु 13.08.2018 को 05:30 अपराह्न से पहले हुई थी।

13. यह हाजीपुर के एक पुलिस अधिकारी अशोक द्विवेदी द्वारा तैयार की गई जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट है। यहां तक कि, प्राथमिकी के अनुसार, गोलीबारी की घटना प्रखंड कार्यालय में 13.08.2018 को दोपहर लगभग 3 बजे हुई थी। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली।

14. सबूतों की भरमार है कि स्थानीय पुलिस थाना प्रखण्ड कार्यालय से केवल 100 गज की दूरी पर स्थित है, जो इस मामले का घटना स्थल है।

15. इसके अलावा, जाँच के बाद, मामला दर्ज किए बिना, अपराह्न 05:45 बजे डॉ. शशिधर कुमार (पी. डब्ल्यू. 4) द्वारा पोस्टमॉर्टम परीक्षा आयोजित की गई। उन्होंने मृतक के

शरीर पर बंदूक की गोली के चार घाव पाए थे, जिनमें से दो प्रवेश के घाव थे और दो अन्य बाहर निकलने के घाव थे। प्रवेश के घाव जले हुए पाए गए। मृत्यु के समय का आकलन पोस्टमॉर्टम परीक्षा से बारह घंटे पहले का अनुमान किया गया था। मौत का कारण बंदूक की गोलियों के कारण रक्तस्राव, सदमा और आघात बताया गया था। मृत शरीर पर यह पोस्टमॉर्टम पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा की गई थी और एक पर्यवेक्षक के रूप में ऑर्थोपेडिक्स के विशेषज्ञ डॉ. हरि प्रसाद भी उपस्थित थे।

16. पीडब्लू 4 के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के समय कोई आकलन नहीं किया जा सका कि क्या चोटें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर लगी थीं। पी. डब्ल्यू. 4 का एकमात्र अवलोकन यह था कि प्रवेश घाव शरीर के ऊपरी हिस्से में थे और निकास घाव निचले क्षेत्र में थे। इसलिए, यह केवल इस बात का संकेत देता है कि जब मृतक को गोली मारी गई थी तो हमलावर मृतक की तुलना में ऊंचे मंच पर थे।

17. जो भी हो, पोस्टमॉर्टम और पीडब्लू 4 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि मृतक की मौत बंदूक की गोलियों के कारण हुई थी। मृत्यु 13.08.2018 को 03:00 अपराह्न के कुछ समय बाद लेकिन अपराह्न 05:30 बजे से पहले हुई थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पुलिस दल भी आ गया था जो जाँच रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम परीक्षा से स्पष्ट है।

18. जो सवाल तुरंत हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि अगर पुलिस थाना प्रखण्ड कार्यालय (घटनास्थल) से केवल 100 गज की दूरी पर स्थित था और पुलिस सदर अस्पताल, हाजीपुर पहुंची थी जहां पोस्टमॉर्टम किया गया था, एकमात्र तार्किक उत्तर कृति प्राथमिकी दर्ज करना होता। वास्तव में, यदि लिखित रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए, तो सूचना देने वाला स्वयं और पीडब्लू 2 मृतक को अस्पताल ले गए थे। हालाँकि, वे दोनों जाँच रिपोर्ट के गवाह नहीं प्रतीत होते हैं। यदि वे मृतक के साथ अस्पताल में थे, तो उनके लिए अर्थात् ओम

प्रकाश साहनी (पीडब्लू 7) और अनिल कुमार साहनी (पीडब्लू 2) के लिए वहां प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए ऐसा कोई कारण नहीं था।

19. इससे हमें संदेह होता है कि क्या एक दिन बाद दायर की गई लिखित रिपोर्ट केवल परामर्श और अपीलार्थियों पर संभावित प्रभाव के बारे में कई विचारों के बाद दर्ज की गई थी। आम तौर पर, प्राथमिकी दर्ज करने में एक दिन की देरी से कोई आलोचना नहीं होगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष को प्राथमिकी देर से दर्ज होने से झटका लगता है।

20. इस मामले की एक और बहुत ही दिलचस्प लेकिन परेशान करने वाली विशेषता यह है कि 13.08.2018 को दो अन्य मामले: एक इस मामले के अन्वेषक द्वारा, अर्थात्, शोभा कांत पासवान (पीडब्लू 9) और दूसरा स्थानीय बी. डी. ओ. द्वारा क्रमशः जनदाहा थाना कांड सं 2018 का 200 और 2018 का 201 दर्ज किए गए थे। ये दोनों मामले लूट, आगजनी और प्रमुख (मृतक) की हत्या के बाद आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए हंगामे के संबंध में थे। इन दोनों प्राथमिकियों में, अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक की हत्या करने का कोई संदर्भ नहीं है।

21. यह फिर से इस कारण से हैरान करती है कि अगर एक प्रमुख की उसके कार्यालय में एक पूर्व प्रमुख और उसके दो सहयोगियों द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो यह खबर पूरे क्षेत्र में सनसनीखेज होती। पी. डब्ल्यू. 9 और स्थानीय बी. डी. ओ. द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों, जिन्हें एक्स और एक्स 1 के रूप में चिह्नित किया गया है, में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया जाना, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप को बहुत संदिग्ध बनाता है।

22. यहां तक कि दोहराव की कीमत पर भी, हम संकेत देते हैं कि अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी पूर्व प्रमुख थे। उनके खिलाफ अविश्वास की कार्यवाही में, मृतक ने पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी हार गए थे।

23. यह जय शंकर चौधरी के झूठे तरीके से फ़साने का कारण भी हो सकता है।

24. अन्य दो व्यक्ति, अर्थात्, अपीलार्थी/राम बाबू साहनी और अभय कुमार, जो आपस में पिता और पुत्र हैं, भी कोई अजनबी नहीं हैं।

25. अपीलार्थी/राम बाबू साहनी की पत्नी ने मुखिया पद के चुनाव में मृतक की मां और पत्नी दोनों को दो अलग-अलग समय पर हराया था।

26. यह तथ्य स्पष्ट रूप से हत्या के एक दिन बाद अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप का कारण स्थापित करता है।

27. राज कुमार साहनी (पीडब्लू. 1) का दावा है कि वह अपना आधार कार्ड बनाने के उद्देश्य से 13.08.2018 को प्रखण्ड कार्यालय गए थे। उन्होंने अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी और एक अज्ञात व्यक्ति को मृतक पर गोली चलाते देखा। इसके बाद वह घर लौट आया। उसने स्वीकार किया है कि पुलिस थाना प्रखण्ड कार्यालय से 100 गज की दूरी पर स्थित है और घटना के सात से आठ दिनों के बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था। घटना के समय बी. डी. ओ. अपने कक्ष में मौजूद थे।

28. उनका बयान कई कारणों से संदिग्ध प्रतीत होता है। एक, घटनास्थल में उनकी उपस्थिति केवल संयोग वश है। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि वह घटना के चश्मदीद गवाहों में से एक था, उसने हत्या के सात से आठ दिनों के बाद पुलिस को अपना बयान दिया। वह मृतक के रिश्तेदार हैं, हालांकि दूर के। सूचक (पीडब्लू 7) के अनुसार, मृतक को बीडीओ के आवास पर बुलाया गया और मृतक अकेला प्रखण्ड कार्यालय वापस आ गया। यह पीडब्लू 1 के बयान को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है कि घटना के समय बीडीओ मौजूद था।

29. इस संदर्भ में संयोग-गवाहों के बारे में एक शब्द आवश्यक होगा क्योंकि अन्य तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी भी इस मामले के संयोग-गवाह प्रतीत होते हैं।

30. संयोग गवाह वह होता है जो किसी अपराध के घटनास्थल में संयोग से होता है और इसलिए, निश्चित रूप से नहीं। दूसरे शब्दों में, आम तौर पर उनके उक्त स्थान पर होने की उम्मीद नहीं है। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति, अपराध के साक्षी होने का संयोग गवाह हो सकता है। कानून बहुत स्पष्ट है कि केवल इसलिए कि एक गवाह संयोग से घटना को देखता है, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसे कई बार अधिक सावधानी के साथ जांचा जाना आवश्यक है।

31. *ए. पी. राज्य बनाम के. श्रीनिवासुलु रेड्डी; (2003) 12 एस. सी. सी. 660*, में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "हत्या के मुकदमे में, यदि" स्वतंत्र गवाहों "को" संयोग गवाह "के रूप में वर्णित किया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि उनका साक्ष्य संदिग्ध है और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध है। गवाहों को उनकी उपस्थिति का अनुरोध करते हुए पूर्व सूचना के साथ हत्याएं नहीं की जाती हैं। यदि हत्या किसी आवास में की जाती है, तो घर के निवासी स्वाभाविक गवाह होते हैं। यदि सड़क पर हत्या की जाती है, तो केवल राहगीर ही गवाह होंगे। उनके साक्ष्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता है या इस आधार पर संदेह के साथ नहीं देखा जा सकता है कि वे केवल "संयोग गवाह" हैं। "संयोग गवाह" शब्द को उन देशों से लिया गया है जहाँ हर आदमी के घर को उसका महल माना जाता है और हर किसी के पास कहीं और या किसी अन्य आदमी के महल में उसकी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह एक ऐसे देश में काफी अनुपयुक्त अभिव्यक्ति है जहां लोग कम औपचारिक और अधिक अनौपचारिक हैं, कम से कम अपनी उपस्थिति की व्याख्या करने में तो ।"

32. उच्चतम न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2009) 9 एस.

सी. सी. 719 मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था।

33. उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामले में, सच्चे लाल तिवारी बनाम उ. प्र. राज्य; (2004) 11 एस. सी. सी. 410 मामले के कानून का उल्लेख करते हुए आगाह किया कि एक संयोग गवाह के साक्ष्य के लिए बहुत सतर्क और बारीक जांच की आवश्यकता होती है और एक संयोग गवाह को घटनास्थल में अपनी उपस्थिति को पर्याप्त रूप से समझाना चाहिए। घटना के बाद संयोग गवाह के आचरण पर भी विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए, खासकर कि क्या उसने अपने गांव या पड़ोस में किसी और को घटना के बारे में सूचित किया था।

34. संयोग गवाह के परिभाषित गुणों को न्यायमूर्ति महाजन ने पूरन बनाम पंजाब राज्य; (1952) 2 एससीसी 454 में समझाया था। यह माना गया था कि "ऐसे गवाहों की आदत होती है कि जब कुछ हो रहा हो तो वे अचानक घटनास्थल पर आ जाते हैं और फिर उस घटना को देखने के बाद गायब हो जाते हैं जिसके बारे में उन्हें बाद में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाता है।"

35. हम पहले ही देख चुके हैं कि पीडब्लू 1 द्वारा प्रखण्ड कार्यालय जाने का उद्देश्य उनका आधार कार्ड तैयार करना था। उन्होंने अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी और एक दूसरे को मृतक पर गोली चलाते देखा था। उनके अनुसार, तीन गोलियां चली थीं और बीडीओ अपने कक्ष में मौजूद था।

36. ये सभी तथ्य अभियोजन पक्ष के मूल संस्करण से असंगत हैं। मृतक को दो गोलियां लगी थीं। बीडीओ घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। और पी. डब्ल्यू. 1 ने घटना के सात से आठ दिन बाद पुलिस के सामने अपना बयान दिया था।

37. कोई भी न्यायालय ऐसी गवाही पर भरोसा नहीं कर सकता है।

38. यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **गणेश भवन पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य; (1978) 4 एससीसी 371** में, जो इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकार है द प्र सं कि धारा 161 के तहत अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी, हालांकि वे गवाह जांच के लिए उपलब्ध थे या हो सकते थे जब जांच अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया था या उसके तुरंत बाद, यह माना गया था कि यह अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है (यह भी देखें - **बालाकृष्ण स्वैन बनाम उड़ीसा राज्य, (1971) 3 एस. सी. सी. 192**; **मारुति राम नाइक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 10 एस. सी. सी. 670** और **जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 689**)।

39. पी. डब्ल्यू. 1 (ऊपर उल्लिखित) भी मृतक से संबंधित है, जो तथ्य हमने नोट किया है।

40. इसी तरह, घटना के एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी **लाल बाबू साहनी (पीडब्लू 5)** जाति-प्रमाण पत्र बनाने के उद्देश्य से प्रखण्ड कार्यालय गए थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने मृतक की हत्या होते देखा। उन्होंने स्वयं इस मामले के जांचकर्ता से संपर्क किया था और उससे कहा कि वह मामले में गवाह होगा। उस खुलासे के बाद ही, घटना के लगभग चार दिन बाद, पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। वह घटनास्थल का निवासी प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में, वह दिल्ली में आजादपुर फ्रूट मार्ट में काम करता था। उसका दावा है कि वह एक महीने पहले ही अपने गाँव के घर वापस आया था। वह भी प्राथमिकी में अभियुक्त व्यक्तियों में से एक था, जिसे हमारे द्वारा संदर्भित किया गया था, और बचाव पक्ष की ओर से एक्स और एक्स 1 के रूप में दर्ज किया गया था।

41. इसी तरह, **लालदेव साहनी (पीडब्लू 6)** अपनी एलपीसी बनाने के लिए 13.08.2018 पर प्रखण्ड कार्यालय आए थे। एक बार फिर मौका गवाह। उनके अनुसार, प्रखण्ड

कार्यालय में 200 से 400 लोग थे। वह इस तथ्य से भी अवगत थे कि मृतक की मां और पत्नी को पहले मुखिया पद के चुनाव में अपीलार्थी/राम बाबू साहनी की पत्नी ने हराया था।

42. इसी तरह, सरोज कुमार सिंह (पीडब्लू 8) का दावा है कि वह कुछ काम के साथ प्रखण्ड कार्यालय गए थे।

43. इन सभी व्यक्तियों ने घटना के कई दिनों बाद पुलिस के सामने अपने बयान दिए हैं। उनके बयान पी. डब्ल्यू. 7 द्वारा लाए गए मूल अभियोजन मामले से भी भिन्न हैं।

44. आइए अब हम सूचक पी. डब्ल्यू. 7 के साक्ष्य की जांच करें। उनकी पृष्ठभूमि पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जानी चाहिए। वह मृतक का बड़ा भाई है और इस मामले का सूचक है। मृतक की हत्या के लगभग आठ महीने बाद, वह निर्विरोध प्रमुख के पद के लिए चुने गए।

45. अपीलार्थियों की ओर से तर्क में सार है कि वह निश्चित रूप से इस बात में रुचि रखते हैं कि मैदान में कोई विरोधी न हो और अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी सबसे शक्तिशाली और दुर्जेय प्रतियोगियों में से एक थे। इसलिए उनके बयान को इस संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है।

46. उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है और स्वीकार किया है कि पुलिस दल 13.08.2018 की शाम को ही अस्पताल पहुंचा था। तब कोई कारण नहीं है कि उन्हें केवल तब ही प्राथमिकी दर्ज नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने घटना का पूरा हिस्सा देखा था और मृतक को, जब वह जीवित था, अस्पताल ले आया था। उनके अनुसार, उन्होंने मृतक के जीवनकाल में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव में, अपने भाई की मृत्यु के बाद, वह निर्विरोध चुने गए। जब उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया था, तब अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी जेल में थे। वह मृतक के साथ प्रखंड कार्यालय आया था। उनके पास

अपना कोई काम नहीं था। पीडब्लू 7 के अनुसार अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने कभी भी जय शंकर चौधरी से प्रखण्ड कार्यालय में प्रमुख के कक्ष के पास उनकी उपस्थिति का कारण नहीं पूछा। वह पहले ही चुनाव हार चुके थे। पीडब्लू 7 ने अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी को किसी भी हथियार से लैस नहीं देखा था। अपने भाई को गोली लगने के बाद, वह अपने भाई के पास गया, लेकिन हमलावरों का कभी पीछा नहीं किया। इसका कारण यह था कि हमलावर पिस्तौल से लैस थे।

47. ये पी. डब्ल्यू. 7 के विरोधाभासी कथन हैं।

48. उन्हें पता नहीं था कि बंदूक की गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस दल प्रखण्ड कार्यालय पहुंचा था या नहीं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक की हत्या के बाद प्रखण्ड कार्यालय में हुई एक घटना के लिए बीडीओ द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बारे में उसे पता था। उस प्राथमिकी में बी. डी. ओ. ने मृतक के किसी भी हमलावर का नाम नहीं लिया था।

49. हत्या के बाद प्रखण्ड कार्यालय में हुए हंगामे के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में भी किसी भी अपीलार्थी का नाम नहीं था।

50. यद्यपि पी. डब्ल्यू. 7 ने स्थानीय राजनीति में पानी का परीक्षण करने के लिए मृतक की हत्या में उनकी रुचि होने के सभी सुझावों का खंडन किया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वह अपीलार्थियों को फंसाने का उद्देश्य रखता था। अन्यथा, घटना के चश्मदीद होने के नाते, उन्हें 13.08.2018 की शाम को ही प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी, जब पुलिस दल अस्पताल में आया था।

51. *दरिया सिंह बनाम पंजाब राज्य; ए आई आर 1965 एस. सी. 328*, में उच्चतम न्यायालय की राय थी कि एक संबंधित या इच्छुक गवाह हमलावर के प्रति प्रतिकूल नहीं हो सकता है, लेकिन यदि वह है, तो उसके साक्ष्य की बहुत सावधानी से और सभी

दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी चाहिए। जहां कोई गवाह पीड़ित का करीबी रिश्तेदार है और उसे अपने हमलावर के प्रति पीड़ित की शत्रुता साझा करते हुए दिखाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से आपराधिक न्यायालयों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे ऐसे गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य की बहुत सावधानी से जांच करें और उस पर भरोसा करने का निर्णय लेने से पहले उस साक्ष्य में सभी दुर्बलताओं की जांच करें।

52. इस तरह के साक्ष्य से निपटने में, अदालत को इस बात की जांच शुरू करनी चाहिए कि क्या उक्त गवाह संयोग से गवाह है या क्या वह वास्तव में अपराध स्थल पर मौजूद था। यदि आपराधिक न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि पीड़ित से संबंधित गवाह संयोग गवाह नहीं था, तो उसके साक्ष्य की संभावनाओं के दृष्टिकोण से जांच की जानी चाहिए और हमले के बारे में उसके द्वारा दिए गए विवरण की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

53. हमारे मन में एक और संदेह है।

54. हमलावरों में से दो, अर्थात् अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी और अभय कुमार पर. अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप है। किसी और को चोट नहीं लगी। ऐसी स्थिति में पी. डब्ल्यू. 7 के इस दावे को स्वीकार करना मुश्किल है कि उन्होंने इस घटना को करीब से देखा था।

55. हमने मृतक के प्रवेश के घावों को जलाने के लिए भी संदर्भित किया है।

56. पोस्टमॉर्टम जाँच रिपोर्ट में दूसरा अवलोकन यह है कि चोटें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ गईं। यह अवलोकन इसलिए था क्योंकि बाहर निकलने के घाव प्रवेश के घावों से नीचे थे। इससे यह आभास होता है कि, शायद, मृतक को तब गोली मारी गई थी जब वह सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और हमलावर एक ऊँचे मंच पर थे।

57. पी. डब्ल्यू. 7 ने अपीलार्थी/जय शंकर चौधरी को हाथ में कोई हथियार लिए हुए भी नहीं देखा था। कुछ ही सेकंडों में गोलीबारी की घटना हो गई। पी. डब्ल्यू. 7 ने किसी को सूचित नहीं किया, जो इस स्थिति में काफी स्पष्ट है कि उनके अपने छोटे भाई को गोली मार दी गई थी, और वे एक निजी अस्पताल गए और उसके बाद सदर अस्पताल, हाजीपुर गए। लेकिन वह पुलिस दल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचने पर भी पुलिस को मामले की सूचना देना नहीं चुनते हैं। हत्या के आठ महीने के भीतर, वह अपने छोटे भाई के स्थान पर प्रमुख के पद के लिए भी चुने गए।

58. ये सभी तथ्य एक साथ मिलकर हमें यह धारणा देते हैं कि पी. डब्ल्यू. 7 पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है।

59. क्या उसने घटना देखी?

60. अगर उसने ऐसा किया, तो वह चमत्कारिक तरीके से बच निकला।

61. उस मामले में, सभी अभियुक्त व्यक्तियों का सटीक नाम लेना और उनमें से पाँच को सबूत के अभाव में बरी हो जाना, उनके साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है।

62. तो क्या वह गलत उद्देश्य से गलत घोषणा नहीं कर रहा है?

63. अभियोजन पक्ष के मामले में ये सभी स्पष्ट विसंगतियां और भौतिक विसंगतियां अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप को अत्यधिक संदिग्ध बनाती हैं। इसलिए, अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए, हम न्यायालय के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करते हैं और अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी करते हैं।

64. अपीलों की अनुमति दी जाती है।

65. सभी अपीलकर्ता जेल में हैं। यदि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है या किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

66. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और रिकॉर्ड के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

67. इन मामलों के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

68. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(राजेश कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति)

कृष्ण/सौरभ

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।